भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 465
जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।
31 आषाढ़, 1948 (शक)

महाराष्ट्र में डिजिटल इंडिया-जेनेसिस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का ब्यौरा

465. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में डिजिटल इंडिया-जेनेसिस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त महाराष्ट्र के टियर-।। और टियर-।।। शहरों में स्टार्टअप, इन्क्यूबेटरों और नवाचार केंद्रों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त राज्य में डिजिटलीकरण और रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप, सरकार और कॉरपोरेट्स के बीच सहयोगात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महाराष्ट्र के गैर-मेट्रो क्षेत्रों में स्टार्टअप लगातार अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, परामर्शदाताओं तक सीमित पहुंच और वित्तपोषण की कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) डिजिटल इंडिया-जेनेसिस के दायरे का विस्तार करने और महाराष्ट्र के टियर-।। और टियर-।।। शहरों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ):
जेनेसिस:
भारत सरकार ने पूरे भारत में टियर- ॥ और टियर- ॥। शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में 'जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस)' योजना का कार्यान्वयन शुरू किया।
इस योजना में पांच वर्षों की अवधि में 490 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 1,600 से अधिक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की खोज, पोषण और विकास करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच) द्वारा 65 इन्क्यूबेटरों के माध्यम से लागू की जा रही है।

जेनेसिस योजना के तहत, महाराष्ट्र में निम्नलिखित तीन इन्क्यूबेटरों को मंजूरी दी गई है:
1. अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) - कृषि विकास ट्रस्ट (एडीटी) बारामती फाउंडेशन, बारामती
2. आईआईएम नागपुर फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (इनफेड), नागपुर
3. विकास और इन्क्यूबेशन काउंसिल (मैजिक) के लिए मराठवाड़ा त्वरक, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)

अब तक, देश भर में कुल 653 स्टार्टअप का समर्थन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र में वित्त पोषण, इनक्यूबेशन, मेंटरिंग, प्रयोगशाला सहायता और अन्य इनक्यूबेशन सेवाओं के साथ समर्थित 24 स्टार्टअप भी शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में इन इन्क्यूबेटरों के माध्यम से योजना के तहत समर्थित स्टार्टअप का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं	**महाराष्ट्र राज्य में इन्क्यूबेटरों के नाम**	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समर्थित स्टार्टअप की संख्या
1	अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) - कृषि विकास ट्रस्ट (एडीटी) बारामती फाउंडेशन, बारामती	6
2	आईआईएम नागपुर फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (इनफेड), नागपुर	12
3	विकास और इन्क्यूबेशन काउंसिल (मैजिक) के लिए मराठवाड़ा त्वरक, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)	6
	कुल	24

इस योजना में स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, उद्योग, निवेशकों, शिक्षाविदों और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर टियर- II और टियर- III शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, जागरूकता, इमर्शन और आउटरीच कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रावधान है।
इस योजना के तहत, राज्य के टियर-II और टियर-III शहरों में उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे 13 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस) योजना के माध्यम से, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) ने महाराष्ट्र के 280+ स्टार्टअप में 6,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के माध्यम से, समर्थित इन्क्यूबेटरों ने महाराष्ट्र के 660+ स्टार्टअप को 115 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है, जबकि स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) के तहत, महाराष्ट्र के स्टार्टअप्स को 325 करोड़ रुपये से अधिक के 115+ ऋण की गारंटी दी गई है।
इसके अलावा, एमईआईटीवाई ने महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की शुरुआत की है जैसे:

- अकोला में कृषि के क्षेत्र में आईओटी हेतु सीओई
- नागपुर में कोर सेक्टर के लिए नेक्स्टजेन इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस में सीओई
- ऑटोमोटिव के लिए सीओई: पुणे में स्वायत्त/कनेक्टेड/इलेक्ट्रिक और शेयर्ड (एसीईएस) वाहन
- पुणे में रिचार्जेबल बैटरी प्रौद्योगिकी (प्री सेल) में सीओई

एमएसएच अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जेनेसिस योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए प्रयोगशालाओं, सह-कार्यस्थलों, सीओई नेटवर्क के संसाधनों, तकनीकी सहायता, डोमेन विशेषज्ञता, संरक्षक समर्थन, निवेशक और बाजार से जुड़ने और नेटवर्किंग तक अभिगम के साथ स्टार्टअप्स का भी समर्थन करता है।

*****